भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †322

सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

एमआईसीई पर्यटन को प्रोत्साहन देना

†322. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में और वैश्विक स्तर पर बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई) से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की भारतीय शहरों को विश्व के शीर्ष एमआईसीई स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में एमआईसीई बाजार से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और वर्ष 2030 तक इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): एमआईसीई पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों के विकास एवं संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय अपने सतत कार्यकलापों के हिस्से के रूप में, सोशल मीडिया और वेबसाइट जैसे विभिन्न माध्यमों से एमआईसीई पर्यटन सहित एक समग्र पर्यटन स्थल के रूप में भारत का संवर्धन करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने एमआईसीई को पर्यटन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में चिह्नित किया है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में एमआईसीई उद्योग जगत के विकास को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमेप भी तैयार किया है। एमआईईसी के रणनीति संबंधी दस्तावेज में निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों को चिह्नित किया गया है:

i. एमआईसीई के लिए संस्थागत सहायता

ii. एमआईसीई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का विकास
iii. भारतीय एमआईसीई उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना
iv. एमआईसीई संबंधी कार्यक्रमों के लिए व्यापार में सुगमता को बढ़ाना
v. भारत की एक एमआईसीई गंतव्य के रूप में मार्केटिंग करना
vi. एमआईसीई उद्योग के लिए कौशल विकास

मंत्रालय ने 'अतुल्य भारत' अभियान के अंतर्गत 'मीट इन इंडिया' को एक विशेष उप-ब्रांड के रूप में पेश किया है। इस उप-ब्रांड का उद्देश्य संवर्धनात्मक पहलों को बढ़ावा देना है, जिसमें भारत को उच्च स्तरीय कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक अवसंरचना, एक जीवंत ज्ञान केंद्र तथा अनेक विशिष्ट पर्यटन आकर्षणों से लैस आकर्षक एमआईसीई गंतव्य के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा।

मंत्रालय ने एक व्यापक डिजिटल एमआईसीई कैटलॉग तैयार किया है जिसमें भारत की अध्यक्षता के दौरान जी20 बैठकों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने वाले 60 से अधिक भारतीय शहरों में उपलब्ध अवसंरचना और सुविधाओं को प्रमुखता से दर्शाया गया है। इस संसाधनपूर्ण कैटालॉग को वैश्विक और राष्ट्रीय एमआईसीई नियोजकों को विश्व के मंच पर प्रमुख गंतव्य के रूप में भारतीय शहरों को बढ़ावा देते हुए भारत में कार्यक्रमों के आयोजन में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।

****